राज्यों में जैव ईंधन के लिए कारगर नीति की आवश्यकता : गोयल

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला

उदयपुर। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने राजस्थान में जैव ईंधन के उत्पादन की पर्याप्त संभावनाओं को मूर्त रूप दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा है कि केन्द्र सरकार को बॉयोडीजल पॉलिसी में राज्यों की बेहतरी के लिए जनहित को ध्यान में रखकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है।

गोयल राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नई दिल्ली के साझे में गुरुवार को उदयपुर में आयोजित 'स्केलिंग अप एंड मैन स्ट्रीमिंग ऑफ बॉयोफ्यूल इन इंडिया' विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के मौके पर बतौर अतिथि संबोधित कर रहे थे। गोयल ने कहा कि राजस्थान सहित देश के अन्य-राज्यों में अनुपयोगी पड़ी भूमि पर बायोफ्यूल के लिए कृषि की व्यापक संभावनाएं हैं।

राज्य में खुले इंस्टीट्यूट

गोयल ने कहा कि राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले प्रदेश में रतनजोत उत्पादन बेहतर बायोफ्यूल का आधार बन सकता है। इसके लिए राजस्थान में विशेष

जैव ईंधन पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित अतिथि।

इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए जमीन देने को तैयार हैं शेष तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन केन्द्र सरकार को देने पर विचार करना चाहिए। बायोफ्यूल सैल के अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री अन्ना साहिब पाटील ने कहा है कि बायोफ्यूल के उत्पादन से जहां डीजल पेट्रोल के विकल्प सृजित होंगे वहीं देश में बढ़ी बेरोजगारी को कम करने में भी इसकी कारगर भूमिका होगी।

बना रहे बायोफ्यूल पॉलिसी

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती वर्षा जोशी ने कहा कि अग्रणी राज्यों एवं दक्ष तकनीकी विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों के अनुभव साझा करते हुए देश के लिए बायोफ्यूल पॉलिसी का नोट तैयार कराया जा रहा है।

समारोह को केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बायोफ्यूल कार्यकारी समूह के अध्यक्ष रामकृष्ण वाई बी ने बायोफ्यूल के लिए व्यावसायिक कृषि एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता की जरूरत बताई।

राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी ने केवल पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को चुनौती बताते हुए सामूहिक चिंतन की आवश्यकता प्रतिपादित की।